P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
Vol-II * Issue-X*June-2015

सडक विकास का डेयरी उद्योग पर प्रभाव

शंकर लाल
व्याख्याता,
भूगोल विभाग,
बी.बी.डी. गर्वन्मेन्ट पी.जी. कालेज,
चिमनपुरा, जयपुर, राजस्थान

महावीर सिंह चौपडा
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान

सारांश

भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वर्तमान में भारत लगभग 135 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। भारत में 'ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम' के बाद दुग्ध उत्पादन में क्रांति आयी है। राजस्थान में 'सरस' ब्रांड नाम से सहकारिता के आधार पर दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में सड़क जाल का महत्वपूर्ण योगदान है। मनरेगा व प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना से सड़कों की पहुंच ढ़ाणीयों तक हुई है। जिससे संकलन केन्द्रों की संख्या बड़ी है, और साथ ही दुग्ध उत्पादन व्यवसाय से अधिक लोग जुड़े हैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में आय का सतत स्त्रोत है। डेयरी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है।

मुख्य शब्द : सामाजिक आर्थिक, सड़क जाल, संकलन केन्द्र, सतत विकास, ऑपरेशन फ्लड, सरस, सहकारिता, अमूल पद्धति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अवशीतन केन्द्र, अभिगम्यता, रोजगार सर्जन, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

डेयरी उद्योग के विभिन्न उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने के लिए परिवहन के कुशल साधनों का होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में सडक मार्गों की उपलब्धता का डेयरी उद्योग पर अधिक प्रभाव पडता है। विभिन्न उत्पादों को विभिन्न दूरियों तक पहुँचाने में परिवहन के साधन और सडक मार्गों की स्थिति प्रभावित करती है। उदाहरणतः ताजे दूध को केवल उतनी दूरी तक ही ले जाया जा सकता है, जितनी दूरी टैंकर या गाडियाँ 8–10 घण्टे में तय कर सकती हैं।

हालांकि वर्तमान में तकनीकी विकास के कारण दूध उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 2005 के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना और नाबार्ड की तरफ से सडक मार्ग निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य सडक मार्गों से जुडाव बढा है। जिसके फलस्वरूप डेयरी उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है।

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर गुजरात के आनन्द सहकारी डेयरी संघ की पद्धति ''अमूल'' पर क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसका ब्रांड नाम ''सरस'' है। राज्य में डेयरी विकास हेतु राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) की स्थापना 1977 में की गई। डेयरी उद्योग क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि नौवीं पंचवर्षीय योजना हुई। जिसके परिणामस्वरूप 2010–11 में 121.8 लाख टन की तुलना में 2011–12 में दूध का उत्पादन लगभग 127.9 लाख टन हुआ। वर्तमान में लगभग 135 लाख टन दूध उत्पादन के साथ भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।

राजस्थान में जहाँ 2004–05 में दूध का कुल उत्पादन 8310 हजार टन था, वह 2012–13 में बढकर 13946 हजार टन हो गया है। डेयरी उद्योग की इस सफलता का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सडक मार्गों का विकास है। भारत में जहाँ 2011–12 में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 290 ग्राम है, वहीं राजस्थान में इसकी उपलब्धता 539 ग्राम प्रति व्यक्ति है।

राजस्थान में डेयरी विकास हेतु संस्थागत ढाँचा

1. **शीर्ष स्तर** : राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेषन ;त्ब्ब्थ्द्ध : इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। राज्य में डेयरी उद्योग विकास कार्यक्रम के संचालन का दायित्व इसी का है। इसका मुख्यालय जयपुर में है।
2. **जिला स्तर** : जिला दुग्ध उत्पादक संघ : वर्तमान में राज्य में इनकी संख्या 21 है। इनका मुख्य कार्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दुग्ध संकलन व इसके उत्पादों का विपणन है
3. **प्राथमिक स्तर** : दुग्ध उत्पादको से दुग्ध संकलन का कार्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ करती हैं। राज्य में इनकी संख्या 2011–12 में 12563 थी।

सडक जाल व दुग्ध उत्पादन

दुग्ध उत्पादक ग्रामीण क्षेत्र में गांव व ढाणियों में निवास करते हैं। जहाँ से दुग्ध संकलन करने, संग्रहण प्लांट तक समय पर पहुँचाने में सडक मार्गों व परिवहन का अत्यधिक महत्व है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, नाबार्ड तथा मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डामर व ग्रेवल सडक बनने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस बढे हुए उत्पादन का मुख्य कारण दुग्ध संकलन है।

राज्य में दुग्ध उत्पादन व सडकों की लम्बाई

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (000टन में)	सडकों की लम्बाई (किमी. में)
2007–08	11377	1,07,442
2008–09	11931	1,12,726
2009–10	12330	1,13,774
2010–11	13234	1,28,350
2011–12	13512	1,29,628

Source

1. Deptt.of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Ministry of Agriculture India.
2. Basic Statistics Rajasthan, 2013

प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता (ग्राम/प्रतिदिन)

2007–08	486
2008–09	501
2009–10	509
2010–11	538
2011–12	539

डेयरी उद्योगों का महत्व

डेयरी उद्योगों से ग्रामोण क्षेत्र में रहने वाले लघु व सीमान्त किसानों को आय का एक निरन्तर स्त्रोत मिला है। विशेषतः महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में डेयरी उद्योग से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। डेयरी उद्योग आज जीविकोपार्जन के साधन से आगे बढकर व्यावसायिक रूप ले रहा है तथा दूध के प्रति किलोग्राम भाव पर नजर डालें तो बढती माँग के कारण दुग्ध के भाव निरन्तर बढ रहे हैं।

(Rs/kg)

2005–06	10.86
2006–07	12.15
2007–08	13.58
2008–09	15.90
2009–10	18.42
2010–11	21.26
2011–12	23.75
2012–13	23.40
2013–14	30.14

Source : Jaipurdairy.com

डेयरी उद्योग की कमियाँ/समस्याएँ

डेयरी उद्योग के विकास पर नजर डालें तो प्रारम्भ में इसके विकास की गति कम थी जो बाद में तेजी से बढो लेकिन फिर भी डेयरी उद्योग के विकास में वर्तमान में निम्न बाधाएँ हैं–

1. **भ्रष्टाचार** : आज भ्रष्टाचार एक बहुत बडी समस्या है। समय–समय पर विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सिंथेटिक दुग्ध टैंकरों से दुग्ध चोरी आदि की खबरें बाती हैं। जिस कारण लोगों में दुग्ध तथा इससे बनने वाले उत्पादों पर भरोसा कम हो गया है।
2. **तकनीक का अभाव** : यूरोपीय देशों में उच्च तकनोक के कारण डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ उच्च तकनीक अभाव के कारण डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं।
3. **शिक्षा का स्तर** : 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 67.06 है जिसमें महिला साक्षरता का प्रतिशत केवल 52.66 ही है।
4. **उन्नत नस्ल के पशुओं की कमी** : राज्य पशु सम्पदा में तो भारत के अग्रणी राज्यों में है लेकिन उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की कमी है।
5. **चारे की कमी**

डेयरी उद्योग विकास की योजनाएँ

1. **मेट्रो डेयरी परियोजना** : बस्सी (जयपुर) में 11 लाख लीटर दूध क्षमता वाली परियोजना जिसकी लागत 100 करोड रूपए है।
2. धौलपुर व टोंक में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना।
3. सीकर जिले में पलसाना में दुग्ध विधायन संयंत्र की स्थापना।
4. **महिला डेयरी परियोजना** : भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्टेप परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 से महिला सषक्तिकरण हेतु इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

निष्कर्ष

इस लेख के माध्यम से हमने जाना कि डेयरी उद्योग के विकास में सबसे अधिक योगदान सडक मार्गों का है। यदि प्रधानमंत्री गाम सडक योजना, नाबार्ड आदि की तरह मनरेगा में भी ग्रेवल व कंक्रीट सडकों की जगह पक्की सडकों का निर्माण किया जावे तो ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक ढाणी ग्राम की पहूँच मुख्य मार्गों तक आसानी से हो जाएगी तो यह डेयरी उद्योग के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत 2015, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. Basic Statistics Rajasthan 2013
3. डॉ. भल्ला आर. एल. – राजस्थान का भूगोल
4. डॉ. सक्सेना हरिमोहन – राजस्थान का भूगोल
5. www.nahi.org
6. www.jaipurdairy.com
7. Deptt. of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Ministry of Agriculture, India